

Protection For Bank Depositors

Bank Deposits upto Rs. 5,00,000/- in respect of each depositor are fully protected by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation under the deposit Insurance Scheme. The Scheme covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) operating in India and also co-operative banks in States and Union Territories to which the Scheme has been extended by the Central Government. These banks are registered as insured banks with the Corporation.

The Corporation's liability in respect of insured deposits will arise in the following cases:

If a bank goes into liquidation: The Corporation will arrange to pay every depositor directly or through the liquidator the amount due to him under the insurance scheme.

If a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle a depositor to get credit for the full amount of his deposit: The Corporation will arrange to pay the reconstructed bank or the amalgamated bank an amount equivalent to the shortfall between the amount due to the depositor under the insurance scheme and the amount of credit received by him under the scheme of reconstruction or amalgamation.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI.

बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा

प्रत्येक जमाकर्ता के पक्ष में रु. 5,00,000 तक की बैंक में जमा राशि डिपॉजिट इश्योरंस स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट बीमा ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। इस योजना में भारत में कार्यरत सभी व्यावसायिक बैंक (प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों समेत) और साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जिनके लिये केंद्र सरकार द्वारा योजना का विस्तार किया गया है। इन बैंकों को निगम के साथ बीमित बैंकों के रूप में रजिस्टर किया गया है।

बीमित जमाकर्ताओं के संबंध में निगम की देयता निम्नलिखित मामलों में उत्पन्न होगी:

अगर बैंक दीवालिया हो जाता है: निगम सीधे या ऋणशोधक के माध्यम से प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था करेगा।

अगर कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ पुनर्गठित या एकीकृत किया जाता है और पुनर्गठन या एकीकरण की योजना जमाकर्ता को उसकी पूरी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती: तो निगम पुनर्गठित बैंक या एकीकृत बैंक को बीमा योजना के अंतर्गत जमाकर्ता को देय राशि और पुनर्गठन या एकीकरण की योजना के अंतर्गत उसे प्राप्त राशि के बीच का अंतर पुनर्गठित या एकीकृत बैंक को देने की व्यवस्था करेगा।

डिपॉजिट इश्योरंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मुंबई (जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, मुंबई)।

बैंक ठेवीदारांसाठी संरक्षण

प्रत्येक ठेवीदाराच्या संबंधात रु.5,00,000/- पर्यंतच्या बँक ठेवी या विमा योजनेच्या अंतर्गत डिपॉजिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन यांच्याद्वारे पूर्णतः सुरक्षित करण्यात येतात. ही योजना भारतामध्ये कार्यरत सर्व व्यापारी बँकांना (यामध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका समाविष्ट) तसेच राज्यातील सहकारी बँका आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठीदेखील छत्र प्रदान करते, केंद्र शासनाने यांच्यासाठी सदर योजना विस्तारित केली आहे. या बँक कॉर्पोरेशनसोबत विमाबद्ध बँका म्हणून नोंदणीकृत आहेत.

विमाबद्ध ठेवीच्या बाबतीत कॉर्पोरेशनचे दायित्व हे पुढील बाबतीत उद्भवेल:

बँकेचे दिवाळे निघाल्यास (परिसमापन झाल्यास): कॉर्पोरेशन ही विमा योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक ठेवीदाराला प्रदेय असणारी रक्कम ही थेटपणे किंवा परिसमापकाद्वारे त्याला प्रदान करण्याची व्यवस्था करेल.

बँकेची पुनर्रचना करण्यात आल्यास किंवा दुसऱ्या बँकेसोबत तिचे एकत्रीकरण करण्यात आल्यास आणि पुनर्रचनेची किंवा एकत्रीकरणाची योजना ही तिच्या ठेवीदाराला पूर्ण रकमेचे क्रेडिट मिळण्यास हक्क प्रदान करत नसल्यास: कॉर्पोरेशन हे ठेवीदाराला विमा योजनेच्या अंतर्गत देय असणारी रक्कम आणि पुनर्रचनेच्या किंवा एकत्रीकरणाच्या योजनेच्या अंतर्गत त्याला प्राप्त झालेली क्रेडिटची रक्कम यांच्यातील तुटीइतकी सममूल्य रक्कम पुनर्रचित किंवा एकत्रीकरण झालेल्या बँकेला प्रदान करण्याची व्यवस्था करेल.

डिपॉजिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन, मुंबई